रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-58/2025/39के-2/22-3-2024-17(184)/22
लखनऊ : दिनांक: 18 मार्च, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/ 2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(च) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल, 2022) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शशिपाल (बन्दी संख्या-6430) पुत्र श्री लाखा सिंह, निवासी नगला वहरी, थाना-वरहन, जनपद-आगरा वर्तमान पता-शान्तिनगर, थाना-लोनी, जनपद-गाजियाबाद, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-909/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 376 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 03-05-2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-08-2007 एवं मा0 उच्चतम न्यायलय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08-07-2021 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07.04.2022 तक 23 वर्ष, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष, 11 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50,000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
2- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
3- **महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।**
4- **जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद/आगरा।**
5- **पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद/आगरा।**
6- **वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।**
7- **नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-4855/2021 शीशपाल उर्फ शशिपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-02-2025 के सन्दर्भ में।**
8- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।**
9- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in